

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

02 जून

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,

देहरादून, दिनांक: 02 जून, 2010

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 187/ XXVII(I)/2010, दिनांक 30 मार्च 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-11, 30 व 31 के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों के अधीन आयोजनागत पक्ष में ₹0 140676000/- एवं आयोजनेत्तर पक्ष में ₹0 91850000/- इस प्रकार कुल ₹0 232526000/- (रुपये तेईस करोड़ पच्चीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, मजदूरी, विद्युत देय, जलकर, किराया, पेंशन, औषधि, भोजन व्यय, पेट्रोल, टेलीफोन आदि आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों एवं समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय तथा वाहन क्रय की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आबंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

- 1- योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- 2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- 3- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
- 4- आबंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
- 5- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

- 6- व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
- 7- स्वीकृत धनराशि की जिलावार फॉट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 8- वित्तीय वर्ष 2010-11 में इसके पूर्ववर्ती वर्षों के एरियर भुगतान यदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।
- 9- अप्रैल, 2009 से नये पदों के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह "क" "ख" "ग" व "घ") की सूचना रखी जाय।
- 10- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 11- निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।
- 12- किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
- 13- बजट मैनुवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 14- वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।
- 15- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पाँच भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा" -02-माध्यमिक शिक्षा एवं 2205-कला एवं संस्कृति-105-सार्वजनिक पुस्तकालय "4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

(3)

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 95(P) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2010 दिनांक: 28 मई, 2010 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या: 803 (1) /XXIV-3/10/02(16)2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव-मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 4- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- निजी सचिव-सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल-पौड़ी/कुमायूँ मण्डल-नैनीताल।
- 10- अपर शिक्षा निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 नरेन्द्र नगर, टिहरी।
- 11- अपर निदेशक, सीमैट, उत्तराखण्ड।
- 12- सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 13- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 14- प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल।
- 15- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- 16- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 17- कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 18- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 19- अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2, 4 एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
- 20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)

उप सचिव।